

## दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 28-06-2025

- » भारत के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में तीव्रता से वृद्धि देखी गई: मेटा
- » भारत-अमेरिका व्यापार समझौता जल्द ही अंतिम रूप लेगा
- » कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर सांख्यिकीय रिपोर्ट
- » भारत की प्रथम समुद्री एनबीएफसी शुरू की गई

### संक्षिप्त समाचार

- » मानसरोवर झील
- » आदि कर्मयोगी कार्यक्रम
- » SPREE योजना
- » परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (VRRR) नीलामी
- » भारत ने चालू खाता अधिशेष की रिपोर्ट की
- » अल्फाजीनोम
- » टेक-वर्स 2025
- » आईबीएटी गठबंधन
- » ग्रीन डाटा सेंटर
- » ढोल (एशियाई जंगली कुत्ता)

### विषय सूची

1	1
5	5
6	6
11	11
12	12
12	12
13	13
14	14
15	15
15	15
16	16
16	16
17	17

## भारत के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में तीव्रता से वृद्धि देखी गई: मेटा

### सन्दर्भ

- मेटा द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में विगत दशक में तीव्रता से वृद्धि हुई है।

### मुख्य बिंदु

- यह भारत के स्टार्टअप्स की वृद्धि के छह प्रमुख कारकों की पहचान करता है, जैसे: एआई को अपनाना, सीमा पार विस्तार, ओम्निचैनल उपस्थिति, टियर 2/3 बाजार विस्तार, श्रेणी विविधता, क्रिएटर-प्रेरित ब्रांड निर्माण।
- एआई एकीकरण: 70% से अधिक स्टार्टअप्स अपने व्यापार संचालन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एकीकृत कर रहे थे।
- हेल्थकेयर, एजटेक और ब्यूटी जैसे सेक्टर्स एआई परिपक्वता में अग्रणी रहे, जो ग्राहक सेवा, पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण, और वैयक्तिकरण के लिए ऑटोमेशन का लाभ ले रहे हैं।
- टियर 2 और 3 बाजारों पर ध्यान: यह नए विकास क्षेत्र के रूप में उभर रहे हैं।
  - स्टार्टअप्स क्षेत्रीय भाषा की सामग्री, स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों, और व्हाट्सएप आधारित कॉमर्स का उपयोग कर रहे हैं।
  - सेवा आधारित स्टार्टअप्स इन बाजारों में उत्पाद आधारित स्टार्टअप्स से पहले प्रवेश कर रहे हैं।

### भारत का स्टार्टअप पारितंत्र

- भारत विश्व के सबसे जीवंत स्टार्टअप पारितंत्रों में से एक है, जिसमें 30,000+ टेक स्टार्टअप्स हैं, जो इसे अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारितंत्र बनाते हैं।
- डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर जनवरी 2025 में 1,59,157 हो गई है।

### DPIIT-Recognised Startups Growth



- वर्ष 2016-2024 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स ने कथित तौर पर 16.6 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं, जो रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान है।

### Industries Leading Job Creation in Startups



Jobs created as of October 31, 2024

- टेक स्टार्टअप्स को कुल फंडिंग के मामले में भारत अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद चौथे स्थान पर है।
- वर्तमान में, देश में 1.4 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं।
- भारत ने अकेले 2024 में छह नए यूनिकॉर्न बनाए।

### महत्व:

- रोजगार सृजन:** स्टार्टअप्स ने देश भर में 1.6 मिलियन से अधिक रोजगारों का सृजन किया है, जो महत्वपूर्ण रोजगार सृजनकर्ता के रूप में उनकी भूमिका को प्रदर्शित करता है।

- जीडीपी वृद्धि को बढ़ावा:** स्टार्टअप नवाचार-संचालित उत्पादकता के माध्यम से जीडीपी में प्रत्यक्ष रूप से और सहायक उद्योगों को बढ़ावा देकर अप्रत्यक्ष रूप से योगदान करते हैं।
- विदेशी निवेश आकर्षित:** भारत वैश्विक उद्यम पूँजी और निजी इक्विटी निवेश के लिए एक चुंबक बन गया है।
- समावेशिता को बढ़ावा:** ग्रामीण-केंद्रित स्टार्टअप और सामाजिक उद्यम स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कृषि में महत्वपूर्ण अंतराल को संबोधित कर रहे हैं, जिससे लाखों लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है।

### सरकारी पहल

- स्टार्टअप इंडिया:** 2016 में लॉन्च किया गया, यह नवाचार को बढ़ावा देने और एक संपन्न स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक प्रमुख पहल है।
  - विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, इसका उद्देश्य स्टार्टअप को आगे बढ़ने और सफल होने के लिए सशक्त बनाना है।
- स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS):** 2021 में लॉन्च की गई, SISFS विभिन्न चरणों में स्टार्टअप का समर्थन करती है, जिसमें अवधारणा का प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण शामिल है।
- स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS):** यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, NBFC और वेंचर डेट फंड से DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है।
- अटल इनोवेशन मिशन (AIM):** NITI आयोग द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य पूरे भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
  - इसमें रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए स्कूल स्तर पर अटल टिंकरिंग लैब्स, एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए अटल इनक्यूबेशन सेंटर और असेवित एवं कम सेवा वाले क्षेत्रों की सेवा के

लिए अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र जैसी पहल शामिल हैं।

- MeitY स्टार्टअप हब (MSH):** यह एक केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो इनक्यूबेशन केंद्रों, उभरती प्रौद्योगिकियों पर उत्कृष्टता केंद्रों और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समर्थित अन्य प्लेटफार्मों के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करता है।
- भारत एआई मिशन (2024):** इसका बजट पाँच वर्षों में ₹10,300 करोड़ है।
  - एक प्रमुख लक्ष्य 18,693 GPU के साथ एक उच्च-स्तरीय सामान्य कंप्यूटिंग सुविधा का निर्माण करना है।
- भारत के AI मॉडल और भाषा प्रौद्योगिकियाँ:** सरकार भारत के अपने आधारभूत मॉडलों के विकास की सुविधा प्रदान कर रही है, जिसमें बड़े भाषा मॉडल (LLM) और भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप समस्या-विशिष्ट AI समाधान शामिल हैं।
- AI उत्कृष्टता केंद्र:** AI स्टार्टअप और अनुसंधान का समर्थन करने के लिए देश भर में समर्पित AI हब एवं नवाचार केंद्र स्थापित करना।
- भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI):** डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण को निजी क्षेत्र के नवाचार के साथ जोड़ता है।

### निष्कर्ष

- पिछले 10 वर्षों में, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम ने जबरदस्त वृद्धि का अनुभव किया है, जो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा बन गया है।
- भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम एक नए परिपक्वता चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसकी पहचान है:
  - स्मार्ट तकनीक-आधारित विकास;
  - क्षेत्रीय समावेशिता;
  - वैश्विक महत्वाकांक्षा;
  - स्थायित्व और उपभोक्ता वैयक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करना।

- ये बदलाव न केवल एक डिजिटल क्रांति को दर्शाते हैं, बल्कि भारत में उद्यमिता के बारे में रणनीतिक पुनर्विचार को भी दर्शाते हैं।

**Source:** TH

## भारत-अमेरिका व्यापार समझौता जल्द ही अंतिम रूप लेगा

### सन्दर्भ

- हाल ही में अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के साथ एक 'बहुत बड़े' व्यापार समझौते की संभावना का संकेत दिया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच वार्ता गति पकड़ रही है।

### भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के बारे में

- पूर्व की भागीदारी:**
  - स्वतंत्रता के बाद:** भारत की संरक्षणवादी नीतियाँ और अमेरिका के शीत युद्धकालीन गठबंधन गहन आर्थिक सहभागिता में बाधक रहे।
  - 1991 सुधार:** भारत की आर्थिक उदारीकरण नीतियाँ एक निर्णायक बिंदु सिद्ध हुईं, जिससे विदेशी निवेश और व्यापार के नए द्वार खुले।
  - 2005–2015:** अमेरिका एक प्रमुख व्यापार भागीदार बनकर उभरा, और द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर वृद्धि हुई।
  - यूएस-इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम (TPF)** जैसे प्रयासों की शुरुआत की गई ताकि विवादों का समाधान हो सके और संबंध मजबूत हों।
- वर्तमान परिदृश्य:**
  - व्यापार मात्रा:** द्विपक्षीय व्यापार \$191 बिलियन तक पहुँच गया है, जिससे अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है।
  - शुल्क तनाव:** अप्रैल 2025 में अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 10% का मूलभूत शुल्क और 26% का पारस्परिक शुल्क प्रस्तावित किया, व्यापार असंतुलन का उदाहरण देते हुए।
  - वार्ताएँ जारी:** दोनों पक्षों के बीच वार्ताएँ तीव्र हो

गई हैं और वे 9 जुलाई 2025 से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं।

### ▲ प्रमुख क्षेत्र हैं:

- कृषि और औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजार तक पहुँच, जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) फसलों की अनुमति शामिल है;
- भारतीय वस्त्र, औषधियों और इलेक्ट्रॉनिक्स पर शुल्क रियायतें;
- डिजिटल व्यापार और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को आसान बनाना।

### भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में प्रमुख चिंताएँ:

- शुल्क असमानताएँ:** भारत G20 देशों में सबसे अधिक औसत लागू शुल्क (~17%) रखने वाले देशों में से एक है, जबकि अमेरिका का औसत लगभग 3.3% है। भारत इन शुल्कों से पूर्ण छूट चाहता है।
- बाजार पहुँच की मांग:** अमेरिका कृषि, डेयरी और औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापक पहुँच चाहता है।
- कृषि और डेयरी संवेदनशीलता:** भारत अपने छोटे किसानों और घरेलू उत्पादकों की सुरक्षा के लिए कृषि और डेयरी क्षेत्रों को खोलने में सर्वानुरूप है।
- ये क्षेत्र राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील हैं और व्यापार वार्ताओं में प्रमुख बाधा बनते हैं।**
- इस्पात और एल्युमिनियम पर शुल्क:** अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से भारतीय इस्पात और एल्युमिनियम निर्यात पर 26% तक के पारस्परिक शुल्क लगाए हैं।
- भारत ने इन उपायों का विरोध किया है और रियायतें माँगी हैं।**
- नियामक और अवसंरचना बाधाएँ:** अमेरिकी नियांतकों को भारत में प्रायः पारदर्शिता की कमी, मूल्य संवेदनशीलता, और अवसंरचनागत अड़चनों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि परियोजना स्वीकृतियों में देरी, असंगत राज्य-स्तरीय नीतियाँ, एवं लॉजिस्टिक्स संबंधी चुनौतियाँ।

- **डिजिटल व्यापार और डेटा स्थानीयकरण:** भारत के डेटा स्थानीयकरण के आग्रह और डिजिटल संप्रभुता के रुख से अमेरिकी टेक कंपनियों में चिंता व्याप्त है।
  - ▲ डिजिटल व्यापार मानदंडों पर सहमति के लिए वार्ताएँ जारी हैं।

### आगे की राह:

- भारत और अमेरिका 2025 के अंत तक एक बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- लक्ष्य है कि द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक \$500 बिलियन तक बढ़ाया जाए, जो कि 2024–25 में \$191 बिलियन था।
- जैसे-जैसे दोनों देश व्यापक व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इसका परिणाम वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को नया आकार दे सकता है, आर्थिक स्थिरता को मजबूती दे सकता है, और समावेशी वैश्वीकरण के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है।

Source: TH

## कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर सांख्यिकीय रिपोर्ट सन्दर्भ

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ‘कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकीय रिपोर्ट (2011-12 से 2023-24)’ का वार्षिक प्रकाशन जारी किया।

### परिचय

- यह एक व्यापक दस्तावेज़ है जिसमें कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों के अंतर्गत फसल, पशुपालन, वानिकी एवं लकड़ी कटाई, तथा मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि क्षेत्रों के उत्पादन मूल्य से संबंधित तालिकाएँ शामिल हैं।

- ▲ यह आंकड़े 2011-12 से 2023-24 तक चालू और स्थिर (2011-12) मूल्यों दोनों पर प्रदान किए गए हैं।

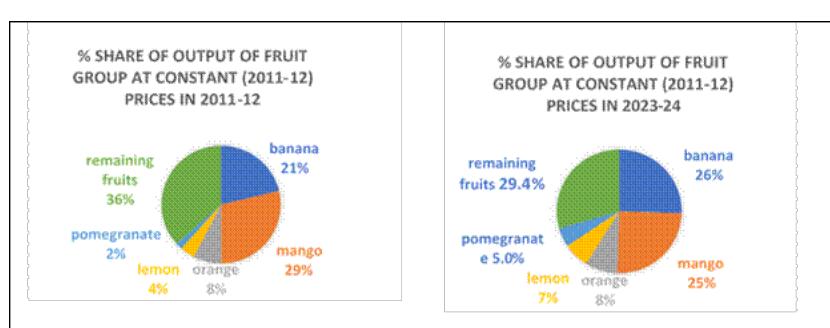
### मुख्य बिंदु

- **कुल वृद्धि:** सकल मूल्य वर्धन (GVA) में चालू मूल्यों पर 225% की वृद्धि दर्ज की गई, जो 2011-12 में ₹1,502 हजार करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹4,878 हजार करोड़ हो गया।
  - ▲ स्थिर मूल्यों पर सकल उत्पादन मूल्य (GVO) में 54.6% की वृद्धि, जो ₹1,908 हजार करोड़ से बढ़कर ₹2,949 हजार करोड़ हो गया।
- **क्षेत्रवार GVO में योगदान (2023-24, स्थिर मूल्यों पर):**

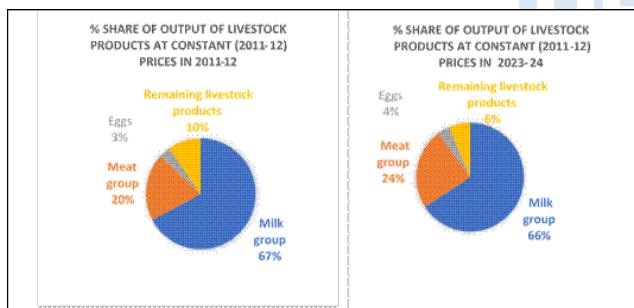
क्षेत्र	GVO में योगदान	उल्लेखनीय रुझान
फसल क्षेत्र	₹1,595 हजार करोड़ (54.1%)	सबसे बड़ा योगदानकर्ता
पशु	₹919 हजार करोड़	सबसे तेजी से बढ़ रहा
वानिकी	₹227 हजार करोड़	मध्यम वृद्धि
मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि	शेयर बढ़कर 7.0% हो गया (4.2% से)	तेजी से बढ़ रहा है

**फसल क्षेत्र का विवरण:** अनाज + फल और सब्जियों ने कुल फसल जी.वी.ओ. में 52.5% का योगदान दिया, धान और गेहूं ने अनाज जी.वी.ओ. में 85% का योगदान दिया।

- **शीर्ष अनाज जी.वी.ओ. राज्य (2023-24):** उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और हरियाणा ने सामूहिक रूप से अनाज जी.वी.ओ. में 53% का योगदान दिया।



- मसाले और मसाले:** शीर्ष राज्य मध्य प्रदेश (19.2%), उसके बाद कर्नाटक (16.6%) और गुजरात (15.5%)।
- पशुधन क्षेत्र:** जीवीओ ₹488 से बढ़कर ₹919 हजार करोड़ हो गया। दूध प्रमुख है, लेकिन हिस्सेदारी 67.2% से घटकर 65.9% हो गई।
  - मांस की हिस्सेदारी 19.7% से बढ़कर 24.1% हो गई है।
- मत्स्य पालन और जलीय कृषि:** योगदान 2011-12 में 4.2% से बढ़कर 2023-24 में 7.0% हो गया।
  - अंतर्देशीय मछली की हिस्सेदारी 57.7% से घटकर 50.2% हो गई है, जबकि समुद्री मछली की हिस्सेदारी 2011-12 से 2023-24 के दौरान 42.3% से बढ़कर 49.8% हो गई है।
  - मत्स्य पालन में जी.वी.ओ. (स्थिर मूल्यों पर) में महत्वपूर्ण बदलाव दो प्रमुख योगदानकर्ता राज्यों पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में देखा गया है।



### महत्व - कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

- जीडीपी और GVA में योगदान:** वर्ष 2023-24 में इस क्षेत्र का भारत के सकल मूल्य वर्धन (GVA) में लगभग 18% योगदान रहा।
- रोजगार सृजन:** यह देश का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है।
  - भारतीय कार्यबल का लगभग 45% कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में संलग्न है (स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण - PLFS 2022-23)।
- खाद्य सुरक्षा:** अनाज, दालें, सब्जियाँ, फल, दुध, मछली एवं पशुपालन उत्पादों के माध्यम से 1.4 अरब से अधिक लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
  - यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और खाद्य सब्सिडी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन की कुंजी है।

- निर्यात में योगदान:** भारत चावल, मसाले, समुद्री उत्पाद, कपास, चाय, कॉफी एवं भैंस के मांस के शीर्ष निर्यातिकों में शामिल है।
- ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन:** ग्रामीण आय में वृद्धि, बुनियादी ढांचे का समर्थन, और खपत में वृद्धि को प्रोत्साहित करता है।
- रणनीतिक एवं राजनीतिक महत्व:** मुद्रास्फीति, ग्रामीण संकट एवं खाद्य मूल्य पर प्रभाव के कारण राजनीतिक स्थिरता में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है।
  - नीतिगत चर्चाओं, बजटीय आवंटनों और चुनावी घोषणापत्रों में कृषि का केंद्रीय स्थान होता है।

### सरकारी पहलें:

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN):** 2019 में शुरू की गई यह केंद्रीय योजना भूमि धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु चलाई जाती है (कुछ अपवादों को छोड़कर)।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY):** 2016 में लॉन्च, यह सरल एवं किफायती फसल बीमा प्रदान करती है ताकि किसानों को सभी अप्रत्याशित प्राकृतिक जोखिमों से सुरक्षा मिल सके।
- कृषि अवसंरचना निधि (AIF):** ₹1 लाख करोड़ की निधि, जो FY 2020-21 से FY 2025-26 तक वितरित की जाएगी; योजना का समर्थन FY 2032-33 तक उपलब्ध रहेगा।
- राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (NBHM):** 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शुरू, इसका उद्देश्य वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करना और “मीठी क्रांति” को साकार करना है।
- नमो ड्रोन दीदी:** यह एक केंद्रीय योजना है (2024-25 से 2025-26 तक) जिसमें 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को ड्रोन दिए जाएँगे ताकि वे किसानों को खाद एवं कीटनाशक छिड़काव जैसी सेवाएँ किराए पर उपलब्ध करवा सकें।

- मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC):** किसानों को उनके खेत की पोषक स्थिति की जानकारी एवं उपयुक्त पोषक तत्वों की खुराक की सिफारिशें प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (NMO)-तेल ताड़:** 2021 में आरंभ, इसका उद्देश्य भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने हेतु तेल ताड़ की खेती को प्रोत्साहित करना है।
- ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार):** APMCs को जोड़ने वाला देशव्यापी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच—इसका लक्ष्य पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण है।
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM):** पशु नस्ल सुधार, चारा विकास एवं पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देता है।
- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY):** मत्स्य क्षेत्र के समग्र विकास पर केंद्रित, जिसमें अवसंरचना, प्रसंस्करण और निर्यात शामिल हैं।

### निष्कर्ष:

- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र केवल खाद्य उत्पादन तक सीमित नहीं हैं—वे भारत की आर्थिक लचीलापन, सामाजिक समता और पारिस्थितिकीय स्थिरता की रीढ़ हैं।
- इन क्षेत्रों को मजबूत करना SDGs की प्राप्ति, समावेशी विकास और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पाने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

Source: PIB

## भारत की प्रथम समुद्री एनबीएफसी शुरू की गई

### समाचार में

- केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री (MoPSW) ने सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड (SMFCL) का उद्घाटन किया।

### सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड (SMFCL)

- इसे पहले सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।

- यह एक मिनी रत्न, श्रेणी-I, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और इसे औपचारिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के रूप में पंजीकृत किया गया है।
- यह समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली एनबीएफसी है।

### क्या आप जानते हैं?

- एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) कंपनी अधिनियम, 1956 या 2013 के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी है।
- यह मुख्य रूप से ऋण, अग्रिम और प्रतिभूतियों में निवेश जैसी वित्तीय गतिविधियों में लगी हुई है। इसमें वे कंपनियाँ शामिल नहीं हैं जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि, उद्योग, वस्तुओं या सेवाओं का व्यापार या अचल संपत्ति है।
- विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जमा एकत्र करने वाली कंपनियों को अवशिष्ट NBFC के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- ऋण देने और निवेश करने में संलग्न होने के बावजूद बैंक और NBFC प्रमुख तरीकों से भिन्न होते हैं: NBFC मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं।
- NBFC भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं हैं और चेक जारी नहीं कर सकते हैं।
- जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) की जमा बीमा सुविधा जमा स्वीकार करने वाले NBFC के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है।

### एसएमएफसीएल का महत्व

- यह समुद्री अमृत काल विजन 2047 के अनुरूप है और इसका उद्देश्य बंदरगाहों, एमएसएमई, स्टार्टअप और समुद्री संस्थानों के लिए वित्तीय अंतराल को पाठना और अनुरूप वित्तीय समाधान प्रदान करना है।
- यह जहाज निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, क्रूज पर्यटन और समुद्री शिक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों का समर्थन करेगा, जिससे आर्थिक विकास और रसद दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।

- यह लॉन्च भारत को एक वैश्विक समुद्री शक्ति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो समावेशी और सतत समुद्री विकास के लिए एक समर्पित वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है।

### भारत का समुद्री क्षेत्र

- यह व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, यह मात्रा के हिसाब से 95% और मूल्य के हिसाब से 70% व्यापार को संभालता है।
- बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय इस क्षेत्र की देखरेख करता है, जिसमें 12 प्रमुख और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह शामिल हैं।
- वित्त वर्ष 24 में, बंदरगाहों ने 818 मिलियन टन कार्गो को संभाला, जो वित्त वर्ष 23 से 4.45% अधिक है।
- सरकार 100% एफडीआई और कर प्रोत्साहन के साथ इस क्षेत्र का समर्थन करती है।
- अमृत काल विजन 2047 बंदरगाहों को वैश्वीकृत करने, अंतर्देशीय/तटीय शिपिंग को बढ़ाने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 पर आधारित है।
- बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) द्वारा जून 2025 में समुद्री और रसद संचालन में क्रांति लाने के लिए सागर सेतु प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था।
- भारत ने 2047 तक विदेशी माल ढुलाई लागत में एक तिहाई की कटौती करने का लक्ष्य रखते हुए अपने बेड़े में 1,000 जहाजों का विस्तार करने के लिए एक नई शिपिंग कंपनी की भी योजना बनाई है।

Source: TH

## संक्षिप्त समाचार

### मानसरोवर झील

#### समाचार

- भारतीय तीर्थयात्रियों का प्रथम जत्था पांच वर्ष के विराम के बाद तिब्बत में मानसरोवर झील पर पहुंचा है, जो पवित्र तीर्थयात्रा की पुनर्संचालन का प्रतीक है।

### मानसरोवर झील

- यह विश्व की सबसे ऊंची स्वच्छ जल की झीलों में से एक है, जो ल्हासा से लगभग 2,000 किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत के दक्षिणी तल पर स्थित है।
- कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में स्थित हैं।
- यह अपने क्रिस्टल-क्लियर नीले तटों और पन्ना हरे केंद्र के लिए जाना जाता है।
- यह हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में पूजनीय है और मुख्य रूप से भारत, तिब्बत और पड़ोसी देशों से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है।

### धार्मिक महत्व मानसरोवर झील

- हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, इस झील का निर्माण भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्रों द्वारा धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए किया था।
- बौद्ध धर्म में, मानसरोवर झील को धन और प्रचुरता के तिब्बती बौद्ध देवता जम्भाला से जोड़ा जाता है।

Source :TH

## आदि कर्मयोगी कार्यक्रम

#### समाचार में

- जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी कार्यक्रम शुरू किया।

#### आदि कर्मयोगी कार्यक्रम के बारे में

- द्वारा शुरू किया गया:** जनजातीय मामलों का मंत्रालय
- उद्देश्य:** नौकरशाहों, ब्लॉक अधिकारियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं सहित आदिवासी कल्याण वितरण में शामिल लगभग 20 लाख हितधारकों को सक्षम बनाना।
- फोकस क्षेत्र:** कार्यक्रम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परिणामों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा जैसे:
  - स्वास्थ्य सेवा अंतराल (सिक्कल सेल रोग पर विशेष ध्यान देने के साथ)
  - स्कूल स्टाफ की कमी

- आदिवासी क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवाओं तक खराब पहुँच
- मिशन कर्मयोगी से संबंध:** जबकि “आदि कर्मयोगी” विशेष रूप से आदिवासी मामलों के लिए है, यह व्यापक “मिशन कर्मयोगी” (2020 में लॉन्च) - राष्ट्रीय नागरिक सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (NPCSCB) के साथ संरखित है।

Source: TH

## SPREE योजना

- समाचार में:** कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की 196वीं बैठक में वर्ष 2025 के लिए इस योजना को पुनः लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में ईएसआई कवरेज का विस्तार करना है।
- SPREE योजना के बारे में:** उद्धव: मूल रूप से 2016 में शुरू की गई SPREE (नियोक्ता/कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना) योजना के अंतर्गत 88,000 से अधिक नियोक्ताओं और 1.02 करोड़ कर्मचारियों का पंजीकरण किया गया है।
- उद्देश्य:** इस योजना का लक्ष्य असंगठित नियोक्ताओं और वंचित कर्मचारियों (जिसमें संविदा एवं अस्थायी कर्मचारी शामिल हैं) को ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत लाना है।
- अवधि:** नवीनीकृत SPREE योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक खुली रहेगी।
- लाभ:** दंड की बजाय स्वैच्छिक अनुपालन पर केंद्रित यह योजना मुकदमेबाजी के भार को कम करने, औपचारिक पंजीकरण को बढ़ावा देने, तथा हितधारकों के बीच बेहतर सहभागिता और सब्दावना को प्रोत्साहित करने का कार्य करेगी।
- एमनेस्टी योजना – 2025:** निगम ने एमनेस्टी योजना – 2025 को भी मंजूरी दी है, जो कि 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक चलने वाली एक एकमुश्त विवाद समाधान खिड़की होगी। इसका उद्देश्य ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत मुकदमेबाजी को कम करना और अनुपालन को प्रोत्साहित करना है।

Source: ET

## परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (VRER) नीलामी

### समाचार में:

- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तरलता प्रबंधन के उद्देश्य से 7-दिन की वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो (VRER) नीलामी आयोजित की।
- इसमें ₹1 लाख करोड़ की अधिसूचित राशि के विरुद्ध ₹84,975 करोड़ की आवेदन प्राप्त हुए हैं और स्वीकार की गईं।
- कट-ऑफ दर 5.49% रही, जबकि औसत भारित दर 5.45% रही, जो यह दर्शाती है कि RBI ने बैंकों से अधिशेष धन किस ब्याज दर पर अवशोषित किया।

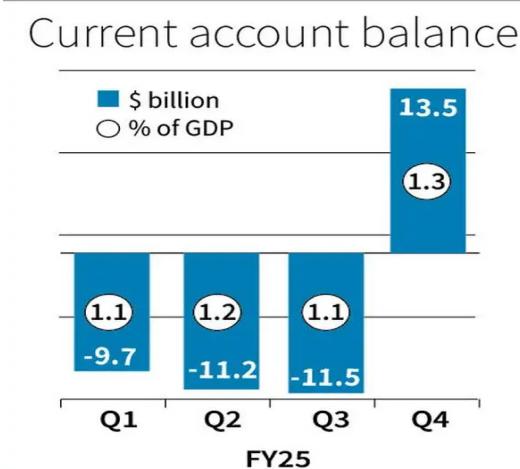
### वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो (VRER):

- यह RBI की तरलता समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility) के अंतर्गत एक अल्पकालिक उपकरण है।
- इसका उपयोग बाज़ार आधारित दरों पर अधिशेष तरलता को अवशोषित करने के लिए किया जाता है।
- यह RBI को मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने और अल्पकालिक ब्याज दरों में उत्तर-चढ़ाव को नियंत्रित करने में सहायता करता है, जिससे इसके प्रभावी तरलता प्रबंधन पर केंद्रित दृष्टिकोण की पुष्टि होती है।

Source: AIR

## भारत ने चालू खाता अधिशेष की रिपोर्ट की सन्दर्भ

- भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, भारत के चालू खाता शेष ने वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में 13.5 बिलियन डॉलर का अपेक्षा से अधिक अधिशेष दर्ज किया।
- सीएबी अधिशेष अपेक्षा से अधिक है, यह इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (इंड-रा) ने रिपोर्टिंग तिमाही में इसके लगभग 7 बिलियन (जीडीपी का 0.7 प्रतिशत) होने का अनुमान लगाया था।



### चालू खाता शेष

- चालू खाता शेष किसी देश के भुगतान संतुलन (BoP) का एक प्रमुख घटक है और यह वस्तुओं, सेवाओं, आय और हस्तांतरण में दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ उसके लेन-देन को दर्शाता है।
- चालू खाते में वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार, प्राथमिक आय (निवेश आय) और द्वितीयक आय (हस्तांतरण और प्रेषण) शामिल हैं।
- चालू खाते में अधिशेष तब होता है जब अंतर्वाह बहिर्वाह से अधिक होता है।

### सीएबी अधिशेष का महत्व:

- मजबूत बाहरी स्थिति को दर्शाता है।
- विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करता है।
- निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है।

Source: TH

## अल्फाजीनोम

### सन्दर्भ

- गूगल डीपमाइंड ने AlphaGenome नाम से एक नया टूल जारी किया है।

### परिचय

- यह एक नया AI मॉडल है जिसे विशेष रूप से इस बात का सटीक अनुमान लगाने के लिए तैयार किया गया है कि मानव DNA में अलग-अलग उत्परिवर्तन उनके कार्यों को कैसे प्रभावित करते हैं।

- यह अत्यंत लंबे DNA अनुक्रमों (1 मिलियन बेस पेयर तक) का विश्लेषण कर सकता है और यह अनुमान लगा सकता है कि आनुवंशिक वेरिएंट जीन विनियमन को कैसे प्रभावित करते हैं।
- यह एकल एकीकृत मॉडल का उपयोग करके, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं और जैविक प्रक्रियाओं में, सामान्य और दुर्लभ दोनों प्रकार के आनुवंशिक वेरिएंट का विश्लेषण करने में सक्षम है।
- इसे बड़े सार्वजनिक जीनोमिक डेटासेट का उपयोग करके प्रशिक्षित किया जाता है।
- उपलब्धता: वर्तमान में गैर-वाणिज्यिक, अनुसंधान-केंद्रित उपयोग के लिए एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (API) के माध्यम से उपलब्ध है।
- अभी तक नैदानिक निदान के लिए स्वीकृत नहीं है।

### महत्व

- AI-संचालित जीनोमिक अनुसंधान में एक बड़ा कदम है।
- गैर-कोडिंग DNA की समझ को बढ़ाता है, जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है लेकिन कैसर सहित आनुवंशिक रोगों के लिए महत्वपूर्ण है।
- बायोसाइंस और सटीक स्वास्थ्य में AI की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

Source: IT

## टेक-वर्स 2025

### समाचार में

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने टेक-वर्स 2025 लॉन्च किया।

### टेक-वर्स 2025

- यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा विकसित भारत 2047 विजन का समर्थन करने के लिए आयोजित पहला प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कार्यक्रम है।
- यह MeitY के प्रमुख R&D संस्थानों- सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC), SAMEER और C-MET को वास्तविक विश्व की

- सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने वाले स्वदेशी नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए एक साथ लाता है।
- यह उत्पाद-संचालित अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव का प्रतीक है और अत्याधुनिक तकनीकों के अनुसंधान, विकास और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए सालाना आयोजित किया जाएगा।

**Source:** PIB

## आईबीएटी (IBAT) गठबंधन

### समाचार में

- IBAT एलायंस ने 2023 से 2024 तक जैव विविधता डेटा में अपने निवेश को दोगुना कर दिया।

### IBAT (एकीकृत जैव विविधता मूल्यांकन उपकरण) एलायंस के बारे में

- 2008 में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस में स्थापित।
- यह बर्डलाइफ इंटरनेशनल, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, IUCN (प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ) और UNEP-WCMC (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र) जैसे चार प्रमुख वैश्विक संरक्षण संगठनों का सहयोग है।
- इसका मिशन डेटा, उपकरण और मार्गदर्शन प्रदान करना है जो संगठनों को जैव विविधता से संबंधित जोखिमों और अवसरों पर कार्य करने में सहायता करता है।
- IBAT डेटा अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की निगरानी करने में सहायता करता है, जिसमें कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (दिसंबर 2022 में अपनाया गया) में उल्लिखित लक्ष्य शामिल हैं।
- मुख्यालय:** यूके

**Source:** DTE

## ग्रीन डाटा सेंटर

### सन्दर्भ

- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने गाजियाबाद के साहिबाबाद में अत्याधुनिक ग्रीन डाटा सेंटर की आधारशिला रखी।

### ग्रीन डेटा सेंटर के बारे में

- एक ग्रीन डेटा सेंटर एक ऐसी सुविधा है जिसे ऊर्जा दक्षता, संधारणीय प्रथाओं और नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए कंप्यूटर सिस्टम एवं संबंधित घटकों (जैसे भंडारण और नेटवर्किंग) को रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  - यह सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (CEL) (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम) और ESDS के बीच सहयोग के माध्यम से स्थापित किया गया है।

### उद्देश्य:

- भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना।
- संधारणीयता विशेषताएँ: ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियाँ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत।**
  - स्मार्ट कूलिंग सिस्टम, परावर्तक छत, वर्षा जल संचयन।
  - पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और प्रति मंजिल 200 उच्च घनत्व वाले रैक का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया।
  - उच्च उपलब्धता और आपदा तन्यकता के लिए टियर III/TIA/अपटाइम-अनुपालक।
  - ग्रीन डेटा सेंटर से स्टार्टअप, उद्यम और सरकारी एजेंसियों को आकर्षित करने की उम्मीद है, जबकि कुशल रोजगार सृजित होंगे और स्थानीय नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
  - सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (CEL)
  - स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण के लिए 1974 में स्थापित।
  - 1977 में भारत का प्रथम सौर सेल और 1978 में भारत का प्रथम सौर पैनल विकसित किया और 1992 में भारत का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया। हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा दिया गया।

**Source:** IE

## ढोल (एशियाई जंगली कुत्ता)

### सन्दर्भ

- भारतीय बन्यजीव संस्थान (WII) के अनुसार, ढोल या एशियाई जंगली कुत्ता (क्यूऑन अल्पाइनस), जिसे कभी स्थानीय रूप से विलुप्त माना जाता था, हाल ही में असम के काजीरंगा-कार्बी आंगलोंग लैंडस्केप (KKAL) में देखा गया।
- पूर्वोत्तर भारत में ढोल की आखिरी बार पुष्टि 2011 में नागालैंड से हुई थी।

### ढोल के बारे में

- सामाजिक व्यवहार:** अत्यधिक सामाजिक; सामान्यत 30 तक के झुंड बनाते हैं, लेकिन शिकार की उपलब्धता के आधार पर अकेले या जोड़े में शिकार कर सकते हैं।

- जीवन काल:** जंगल में 10-13 वर्ष ; कैद में 16 वर्ष तक।
- खतरे:** प्रमुख खतरों में निवास स्थान का नुकसान, शिकार की कमी, उत्पीड़न, बीमारी और अन्य शिकारियों के साथ प्रतिस्पर्धा शामिल है - जिससे जनसंख्या विखंडन होता है।
- वितरण:** अब भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया सहित मध्य और पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों तक सीमित है।
- संरक्षण स्थिति:** इसे CITES - परिशिष्ट II में शामिल किया गया है।
- ढोल को IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

Source: TH

